भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 572

03 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

धान किसानों का कल्याण

572. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस वर्ष धान की खरीद में हुई देरी और कम खरीद के कारण श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में किसानों के सामने आ रही समस्याओं की जानकारी है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा किसानों से धान की खरीद सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में धान की खरीद का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा धान किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने और धान खरीद में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) मोड के तहत राज्य में एमएसपी पर धान की खरीद के लिए कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं होने के कारण, राज्य सरकार ने खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2025-26 के दौरान धान की खरीद नहीं करने का निर्णय लिया है।

(ग): राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान एमएसपी पर धान की कोई खरीद नहीं की गई है।

(घ): भारत सरकार ने राज्य सरकार के ऑनलाइन खरीद पोर्टल के माध्यम से किसानों से धान, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की खरीद की प्रणाली शुरू की है और सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा किसानों को उनके बैंक खाते में एमएसपी का सीधा ऑनलाइन भुगतान अधिमान्य रूप से खरीद के 48 घंटों के भीतर करने का अनिवार्य प्रावधान किया है।

*****